

the Bankura and Purulia districts at an estimated cost of Rs. 22.86 crores.

No project report on Upper Darakeswar project has been received from the State Government so far.

तेनु तथा कोनार बांधों से 'लिफ्ट' सिंचाई

4647. श्री राम दास सिंह : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार छोटा नागपुर (बिहार) के पहाड़ी क्षेत्रों के तेनू और कोनार बांध से, जहाँ नहर से और बहुत हद तक कुंए से सिंचाई नहीं हो सकती, सिंचाई का प्रबन्ध 'लिफ्ट' द्वारा करेगी ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसका औचित्य क्या है, और छोटा नागपुर में सिंचाई का दूसरा तरीका क्या हो सकता है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) : सिंचाई राज्य विषय है, इसलिए सिंचाई परियोजनाओं का आयोजन, अन्वेषण तैयार करना और कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। बिहार सरकार ने छोटा नागपुर के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए तेनू और कोनार बांधों से लिफ्ट सिंचाई की कोई स्कीम केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत नहीं की है। लेकिन राज्य सरकार ने छोटा नागपुर के हजारी बाग और धनवाढ़ जिलों के क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोनार व्यपवर्तन स्कीम, गोबई बराज स्कीम और खुदिया सिंचाई स्कीम, नामक एक बृहद और दो मध्यम सिंचाई स्कीमों का प्रस्ताव किया है। इसके अलावा, तेनूघाट बांध परियोजना से धनवाढ़-गिरिडीह की जनजाति पट्टी में लगभग 1600 हेक्टर क्षेत्र को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध होने का अनुमान है।

उत्तर प्रदेश में भूमि विकास बैंक से छोटे किसानों को ऋण

4648. श्री राम नरेश कुशबाहा : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश भूमि विकास बैंक केवल उन किसानों को ट्रेक्टर के लिए ऋण देते हैं जिनके पास 12½ एकड़ भूमि हो, जिससे उससे कम जमीन वाले लोग इस सुविधा से वंचित हो जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश भूमि विकास बैंक के माध्यम से छोटी जोत वाले किसानों को ऋण सुविधायें दिलाने की व्यवस्था कर रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक केवल उन किसानों को ट्रेक्टर के लिए ऋण देता है जिनके पास 12½ एकड़ भूमि है और 12½ एकड़ से कम भूमि वाले किसान अकेले ही ट्रेक्टर के लिए ऋण पाने के पात्र नहीं ह। लेकिन 12½ एकड़ से कम भूमि वाले छोटे किसानों को इस शर्त पर सामूहिक ऋण पाने की अनुमति है कि समूह के सदस्यों द्वारा बैंक को वंधक हेतु दी गई कुल भूमि 12½ एकड़ दोहरी मफल वाली भूमि से कम नहीं है।

प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा पर खर्च

4649. डा० रामजी सिंह : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा (तकनीकी और विश्वविद्यालय शिक्षा और अनुसंधान सहित) पर क्रमशः कितनी-कितनी धनराशि खर्च की जा रही है ;

(ख) क्या उपरोक्त खर्च संतुलित तरीके से किया जा रहा है, यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय हित में इस अनुचित झुकाव को ठीक करने का है, यदि हां, तो कैसे ; और

(ग) सरकार को शिक्षा शुल्क से कुल कितनी आय होती है और क्या जिस वर्ग से शिक्षा शुल्क लिया जाता है, उस वर्ग पर पर उसी अनुपात में खर्च किया जाता है।

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रकाश चन्द्र चन्द्र) : (क) राज्यों/संघ शासित प्रदेशों और केन्द्र के संबंध में प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा पर 1976-77 राजस्व खाते के लिए बजट में रखा गया व्यय इस प्रकार है :—

(रुपय हजारों में)

| | |
|---|---------|
| प्राथमिक शिक्षा | 8660650 |
| माध्यमिक शिक्षा | 5800512 |
| उच्च शिक्षा (तकनीकी तथा विश्वविद्यालय और अनुसंधान सहित) | 3665395 |

(ख) राज्य अपनी अपनी निजी व्यय पद्धतियों का निर्णय अपनी अपनी आवश्यकताओं के आधार पर करते हैं।

(ग) शिक्षा पर कोई केन्द्रीय उपकर नहीं है।

मध्य प्रदेश में सघन भेड़ विकास कार्यक्रम

4650. श्री लक्ष्मी नारायण नायक : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सघन भेड़ विकास कार्यक्रम के लिये मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों का चयन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए तैयार किये गए कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या इस कार्यक्रम में बकरियों के विकास को भी शामिल किया गया है ; और

(घ) यह कार्यक्रम कब आरम्भ किया गया था और इस के लिये वार्षिक अनुमानतः कितनी धन राशि मंजूर की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

Water Rates charged by DDA in Rajauri Garden, D. D. A. Colonies

4651. SHRI JAGANNATH SHARMA: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) the water rates charged by the DDA in the Rajauri Garden (G-8 Area) DDA colonies;

(b) whether these rates are four times more than the rates charged by the Delhi Municipal Corporation;

(c) the reasons for these enhanced rates;

(d) whether the Welfare Agencies of these colonies had met the Vice-Chairman and whether he assured them that these rates would be reduced with retrospective effect; and

(e) if so, whether Government have asked the authorities not to harass the residents till a final decision is taken?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) The Delhi Development Authority is charging 70 paise per